



2026:AHC:128500

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19836/2026

शीलेन्द्र उर्फ भोला

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: मनीष यादव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना- अवागढ़, जिला- एटा में मुकदमा अपराध संख्या 67/2026, बी.एन.एस. की धारा 309(2), 352, 115(2), 317(2) तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। बस संख्या यू.पी. 78 जेटी 0801 के पीड़ित/परिचालक द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है। विवेचना के दौरान, पीड़ित ने आवेदक का नाम अभियुक्त के रूप में नहीं लिया। अभियोजन द्वारा आवेदक को कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई शिनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई तथा बस चालक को कथित रूप से लगी चोटें साधारण प्रकृति की थीं। सूचनादात/पीड़ित के कान की बाहरी सतह के दाहिनी ओर मात्र एक खरोंच की चोट थी। आवेदक का नाम विवेचना के दौरान दिनांक 28.03.2026 को साक्षी विनोद के बयान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में प्रकाश में आया। आवेदक को कथित अपराध से जोड़ने के लिए उसके कब्जे से 1170/- रुपये, एक मोबाइल फोन तथा एक देसी पिस्तौल की झूठी बरामदगी दिखाई गई। यह अपराध विशेष रूप से मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है। वर्तमान प्रकरण में आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आगे यह तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त विपिन को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 19881/2026 में दिनांक 16.06.2026 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक दिनांक 29.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगते गए कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने का वाद बनता है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- शीलेन्द्र उर्फ भोला को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दायर करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा, जब न्यायालय में गवाह उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 229-ए/ बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82/ बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार भा.द.सं. की धारा 174-ए/ बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद शुरू होने, (2) आरोप विरचित करने और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313/ बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करना खुला होगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां साक्षीगण की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

22 जून, 2026

ए.पी.पांडेय